भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 630

29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में विकार्बनीकरण (डिकार्बनाईजेशन)

630. श्री मिथलेश कुमार:
श्री आदित्य प्रसाद:
सुश्री कविता पाटीदार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र में विकार्बनीकरण और संसाधन दक्षता में सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (ख): सरकार द्वारा इस्पात उद्योग में विकार्बनीकरण और संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) इस्पात मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के आधार पर ''भारत में इस्पात क्षेत्र का हरितीकरण: रोडमैप और कार्य योजना'' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का विस्तृत विवरण, इस्पात क्षेत्र के विकार्बनीकरण के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा और उक्त के लिए रणनीति, कार्य योजना और रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया है। इस मिशन में इस्पात मंत्रालय एक हितधारक है तथा इसके द्वारा मिशन के अंतर्गत वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए डीआरआई के उत्पादन के लिए दो पायलट परियोजनाएं और कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु एक पॉयलट परियोजना सौंपी गई है।

(3) इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण परियोजना, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू रूप में उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करती है।

(4) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021, इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करता है।

(5) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।

(6) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

****